शास्त्री की भविष्यवाणी:
इस टीम के हाथ जाएगा
T20 विश्व कप 2026

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

क्राइम, सस्पेंस और
ट्रॉमा की गहराई में
उतरती भूमि पेडनेकर

Page-05

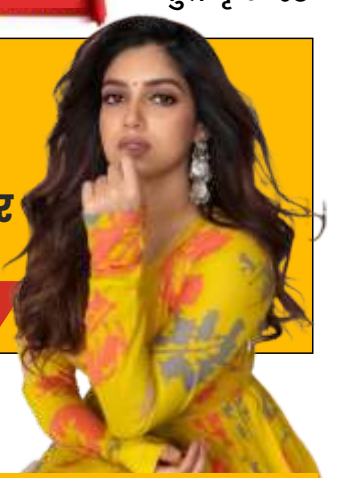

NOTAM जारी – सुरक्षा अलर्ट बढ़ा

राजस्थान में वायुसेना के जेट्स का अभ्यास

इंडियन एयरफोर्स अपनी युद्धक क्षमताओं और मारक शक्ति को परखने के लिए राजस्थान के रेतीले इलाके में साल 2026 का सबसे बड़ा हवाई शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है. इस दौरान न केवल एयरफोर्स के जांबाज पायलट अपना कौशल दिखाएंगे, बल्कि दुनिया के सामने भारत की बढ़ती फायर पावर और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का भी प्रदर्शन होगा. एयरफोर्स फरवरी 2026 में अपनी सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित फायर पावर एक्सरसाइज 'वायुशक्ति-2026' का आयोजन करेगी. इंडियन एयरफोर्स का युद्धाभ्यास पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के पोखरण इलाके में होगा. इसके लिए NOTAM जारी कर दिया है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हवाई गतिविधियां होने वाली हैं. इस अभ्यास के जरिए इंडियन एयरफोर्स अपनी युद्धक तैयारियों, आधुनिक हथियार प्रणालियों और ऑपरेशनल क्षमता का व्यापक प्रदर्शन करेगी. वायुशक्ति एक्सरसाइज का आयोजन हर कुछ वर्षों में किया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य एयरफोर्स की फायर पावर, सटीक हमला करने की क्षमता और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के बीच तालमेल को परखना होता है. अबकी बार की वायुशक्ति इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद आयोजित हो रही है और इसका दायरा पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक होगा. NOTAM के अनुसार, यह

अभ्यास तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा. पहले दो चरणों में ग्राउंड लेवल से लेकर 30,000 फीट तक हवाई गतिविधियां होंगी. अंतिम चरण में ऊंचाई की सभी सीमाएं हटा दी जाएंगी, जिससे वायुसेना फुल-स्केल कॉम्बैट सिमुलेशन और लॉन्ग-रेंज स्ट्राइक का अभ्यास कर सकेगी.

बंगाल में ममता को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने बनाया चुनाव वॉर रूम

जैसे-जैसे पश्चिम बंगाल में मार्च-अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो रही है. सत्ता, पहचान और महत्वाकांक्षा की इस जटिल लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) खुद को एक निर्णायक मोड़ पर पाती है. पार्टी का लक्ष्य है पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की मजबूत पकड़ से छीनना. पश्चिम बंगाल में सत्ता से बीजेपी अब तक दूर रही हैं पर वहां के राजनीतिक हालात तेजी से बदलते दिख रहे हैं. जहां 2021 के चुनाव नतीजों ने दिखाया कि बीजेपी वोट प्रतिशत में अभी भी टीएमसी से करीब 10 फीसद पीछे है. हालांकि 2016 में केवल 4 सीट पाने वाली बीजेपी ने 2021 के चुनाव में 294 में से 77 सीटें हासिल की जो पार्टी की असाधारण बढ़त को दिखाता है- वो भी हिंदी पट्टी से बाहर. बीजेपी की चुनावी कहानी इस बार सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी राजनीति से भी तय होगी. 30 और 31 जनवरी को अमित शाह की प्रस्तावित बंगाल यात्रा का मकसद है- पार्टी में एकता मजबूत करना और गुटबाजी खत्म करना. पश्चिम बंगाल जैसे राजनीतिक रूप से उथल-पुथल वाले राज्य में अंदरूनी कलह किसी भी अभियान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है.

सुनैत्रा नहीं तो प्रफुल्ल पटेल:

अजित पवार की साख से तय होगी पार्टी की दिशा

प्रफुल्ल पटेल का राजनीतिक सफर चार बार लोकसभा और छह बार राज्यसभा सांसद के रूप में एक बेहद प्रभावशाली और अनुभवी नेतृत्व का रहा है.उन्होंने 10वीं (1991), 11वीं (1996), 12वीं (1998) और 15वीं (2009) लोकसभा में भंडारा-गोंदिया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया.

महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों पॉवर शब्द के इर्द-गिर्द सिर्फ एक ही परिवार की चर्चा है पवार परिवार. लेकिन अजित पवार गुट के भीतर चल रही हलचल इशारा कर रही है कि अगर सुनेत्रा पवार की ताजपोशी में कोई पेंच फंसता है, तो नेक्स्ट इन लाइन सिर्फ एक ही नाम है—प्रफुल्ल पटेल! लेकिन राजनीति में आगे क्या होगा इसके लिए सही समय के आने का इंतजार करना होता है. कहा तो ये भी जाता है कि राजनीति में जो तस्वीर साफ दिख रही हो उसे तब तक साफ नहीं मान लेना चाहिए जब तक उसे लेकर कोई औपचारिक ऐलान ना हो जाए. सियासी गलियारों में चर्चा है कि यदि तकनीकी या राजनीतिक कारणों से सुनेत्रा पवार को जिम्मेदारी नहीं मिलती, या वो ख़ुद अगर पॉवर-प्ले की जंग में उतरने से मना कर दें तो प्रफुल्ल पटेल सबसे स्वाभाविक पसंद होंगे. इसके पीछे कई ठोस वजहें उनकी चाणक्य और संकटमोचक वाली छवि है !प्रफुल्ल पटेल की सबसे बड़ी ताकत उनका दिल्ली कनेक्शन है. यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे पटेल के संबंध सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के बड़े नेताओं से बहुत गहरे हैं. बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी सीधी ट्यूनिंग अजित पवार गुट के लिए एनडीए के भीतर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है राजनीतिक करियर में उन्होंने नागरिक उड्डयन और भारी उद्योग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभालते हुए केंद्र सरकार में अपनी छाप छोड़ी है.प्रफुल्ल पटेल का राजनीतिक सफर चार बार लोकसभा और छह बार राज्यसभा सांसद के रूप में एक बेहद प्रभावशाली और अनुभवी नेतृत्व का रहा है. उन्होंने 10वीं (1991), 11वीं (1996), 12वीं (1998) और 15वीं (2009) लोकसभा में भंडारा-गोंदिया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया. राज्यसभा में उनका कार्यकाल 2000, 2006, 2014, 2016, 2022 और हाल ही में 2024 में शुरू हुए छठे कार्यकाल सहित कुल छह बार रहा है. मंत्री पदों की बात करें तो उन्होंने 2004 से 2011 तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) और 2011 से 2014 तक केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो संभाले हैं. उनकी बड़ी उपलब्धियों में भारतीय विमानन क्षेत्र का आधुनिकीकरण और एयर इंडिया का विस्तार शामिल है, जिसके लिए उन्हें 2005 में 'एविएशन मिनिस्टर ऑफ द ईयर', "रिफॉर्मर ऑफ द ईयर" जैसे सम्मानों से नवाजा गया. इन उपलब्धियों के साथ साथ वो शरद पवार के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार के रूप में दिल्ली के सत्ता गलियारों में विपक्षी एकता और गठबंधन की राजनीति के 'चाणक्य' माने जाते रहे. पटेल के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है. पार्टी के भीतर वे एक सर्वमान्य चेहरा हैं. यदि सुनेत्रा पवार के नाम पर परिवारवाद का आरोप लगता है, तो प्रफुल्ल पटेल को आगे कर मेरिट और अनुभव का कार्ड खेला जा सकता है. अजित गुट में इस समय दो विचारधाराएं काम कर रही हैं. एक सोच है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाकर महिला कार्ड और इमोशनल कार्ड खेला जाए, वहीं दूसरी सोच है कि प्रफुल्ल पटेल जैसे अनुभवी हाथ ही महाराष्ट्र के कठिन सियासी समीकरणों में पार्टी को सही दिशा दिखा पाएंगे.

संदिग्ध मौत मामला:

साध्वी प्रेम बाईसा केस की जांच अब SIT के हवाले

जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनकी मृत्यु का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस हत्या, आत्महत्या और अन्य संभावित कारणों के सभी पहलुओं से जांच कर रही है. मेडिकल बोर्ड द्वारा कराए गए पोस्टमार्टम के बाद अब रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार है. पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की साजिश के आरोप को लेकर सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है.उन्होंने बताया कि साध्वी प्रेम बाईसा को इंजेक्शन देने वाले कंपाउंडर देवी सिंह से पूछताछ की जा चुकी है. पुलिस कमिश्नर के मुताबिक जांच के दायरे में प्रेम बाईसा के पिता और आश्रम के अन्य सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा और उनसे भी पूछताछ की जाएगी. जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनकी मृत्यु का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस

हत्या, आत्महत्या और अन्य संभावित कारणों के सभी पहलुओं से जांच कर रही है. मेडिकल बोर्ड द्वारा कराए गए पोस्टमार्टम के बाद अब रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार है. पुलिस अब तक सामने आए सभी साक्ष्यों को खंगाल रही है. मौत के वास्तविक कारणों को लेकर स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगी और फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

आवश्यकता

Tv भारतवर्ष ग्रुप

को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में e रिपोर्टर की। और पॉडकास्ट हेतु टैलेंटेड युवक ,और युवतियों की जो डिजिटल मीडिया में अपना भविष्य और पहचान बनाना चाहते है ।

इच्छुक अभ्यर्थी अपनी सीवी
8601780000 व्हाट्सप्प के माध्यम से भेंजे

वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग आवश्यक

आयोग के सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्याउपाने ने एएफपी को बताया, और कहा कि रसद, प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाएं योजना के अनुसार आगे बढ़ रही हैं। वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद 3 करोड़ लोगों के देश का मार्गदर्शन करने के लिए एक अंतरिम सरकार के गठन के बाद चुनाव कराए गए थे।

दुनिया का थानेदार अमेरिका और उसका विकल्प बनने की चाहत रखने वाले चीन समेत अन्य विघ्नसंतोषी देशों को शांतिप्रिय व गुटनिरपेक्ष देश भारत ने एक नहीं बल्कि कई बार स्पष्ट कूटनीतिक संदेश दिए हैं कि वैश्विक समस्याओं का समाधान पारस्परिक सहयोग से ही संभव है, टकराव से कतई नहीं लेकिन उनकी शहंशाही प्रवृत्ति है कि मानती नहीं बल्कि तरह तरह से भारत को घेरने या चिढ़ाने की कोशिश करती रहती है। यही वजह है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाले नए भारत ने ऐसे देशों की अनदेखी, अनसुनी करते हुए अपनी सकारात्मक पहलों से अक्सर चौंकाने वाले परिणाम देने शुरू कर दिए हैं, जिससे भारत की प्रतिष्ठा और साख दोनों में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है।

खासकर, वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, महामारी और गरीबी का समाधान सहयोग से ही संभव है क्योंकि ये सीमाओं से परे हैं। पारस्परिक युद्धों की तरह इन मुद्दों पर टकराव ऐसी समस्याओं को बढ़ाता ही है, जबकि अंतरराष्ट्रीय साझेदारी संसाधनों और प्रयासों को एकजुट करती है। यदि पारस्परिक सहयोग के कतिपय प्रमुख उदाहरणों की बात की जाए तो साल 2019 की अंतरराष्ट्रीय महामारी कोविड-19 के वैक्सीन के विकास में वैश्विक सहयोग ने रिकॉर्ड समय में टीके तैयार किए, जैसे COVAX पहल और वैज्ञानिकों की अंतरराष्ट्रीय साझेदारी ने। कहना न होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), Gavi, CEPI और UNICEF के सह-नेतृत्व में COVAX ने COVID-19 टीके 146 देशों को 2 अरब खुराकें वितरित कीं, जिससे निम्न-आय वाले देशों में 2.7 मिलियन मौतें टलीं। इसप्रकार यह पहल वैश्विक महामारी प्रबंधन का एक उत्कृष्ट मॉडल बनी। इससे पहले पेरिस समझौता ने 2015 से ही देशों को एकजुट कर जलवायु लक्ष्य निर्धारित करने में सफलता पाई जिससे नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बढ़ा। देखा जाए तो जलवायु पर पेरिस समझौता (2015) ने 196 देशों को वैश्विक तापमान वृद्धि 2°C से नीचे रखने के लक्ष्य पर एकजुट किया जिससे नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बढ़ा। यह UNFCCC के तहत बहुपक्षीय सहमति का प्रतीक है। वहीं संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर्यावरण और शांति के लिए विशेष समूह गठित कर साझेदारी को बढ़ावा देते हैं। जहां तक पारस्परिक टकराव के नकारात्मक प्रभाव की बात है तो रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक अनाज आपूर्ति बाधित कर 27.6 करोड़ लोगों को भुखमरी की कगार पर पहुंचाया।

चतुर चीन ने अमेरिका में घुसकर चुरा लिए टॉप सीक्रेट, गूगल का AI टूल बना हथियार

चीन के जासूस अमेरिका में घुसकर उसे अंदर से कुरेद रहे हैं, खुफिया जानकारी निकालकर चीन भेज रहे हैं. ऐसा ही एक और मामला सामने आया है. अमेरिकी न्याय विभाग ने गुरुवार, 29 जनवरी को कहा कि Google के पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिनवेई डिंग को AI से जुड़ी खुफिया जानकारी चुराकर चीन भेजने के लिए दोषी ठहराया गया है. यह पाया गया कि लिनवेई डिंग चीन की दो कंपनियों के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा था. वह अमेरिकी की टेक जायंट कंपनी Google में शामिल हुआ और वहां से AI ट्रेड सीक्रेट चुराकर वह वापस दोनों चीनी कंपनियों को भेजता था. 38 साल के चीनी नागरिक डिंग ने हजारों पन्नों की गोपनीय जानकारी चुराई है. उसे आर्थिक जासूसी के सात मामलों और व्यापार रहस्यों (ट्रेड सीक्रेट) की चोरी के सात मामलों में दोषी पाया गया है. उसपर 11 दिन की सुनवाई हुई. हर आर्थिक जासूसी आरोप में अधिकतम 15 साल की जेल की सजा और $5 मिलियन का जुर्माना है. जबकि हर ट्रेड सीक्रेट के आरोप में अधिकतम 10 साल की सजा और $250,000 का जुर्माना है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार डिंग को मूल रूप से मार्च 2024 में ट्रेड सीक्रेट की चोरी के चार मामलों में दोषी ठहराया गया था. फरवरी में एक सुपरसीडिंग अभियोग ने आरोपों का विस्तार किया. डिंग के मामले को बाइडेन सरकार द्वारा 2023 में बनाई गई एक इंटरएजेंसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी स्ट्राइक फोर्स के माध्यम से कॉर्डिनेट किया गया था.

निपाह वायरस के जरिए भारत को बदनाम करने की बड़ी साजिश?

ट्रंप की पत्नी मेलानिया के जीवन पर बनी सबसे महंगी डॉक्यूमेंट्री फिल्म

डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'मेलानिया' 30 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. मगर द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूनाइटेड किंगडम में 'मेलानिया' की ओपनिंग फ्लॉप रहने की आशंका है. यह फिल्म ब्रिटेन के 100 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ब्रिटेन की सबसे बड़ी सिनेमा चेन में से एक, वू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम रिचर्ड्स ने बताया कि लंदन के इस्लिंगटन स्थित मुख्य सिनेमाघर में शुक्रवार को दोपहर 3:10 बजे के शो के लिए केवल एक टिकट बिका है और शाम 6 बजे के शो के लिए दो टिकट बुक किए गए हैं. यह डॉक्यूमेंट्री ट्रंप के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह से पहले के 20 दिनों के दौरान मेलानिया के जीवन को दर्शाता है और उनके प्रोफेशनल और निजी जीवन की दुर्लभ झलकियां प्रस्तुत करता है. इसमें राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में मेलानिया ट्रंप की भूमिका को दिखाया गया है,

जिसमें उनके शपथ ग्रहण भाषण के लहजे पर उनका प्रभाव भी शामिल है. साथ ही, शपथ ग्रहण समारोह के उन खास पलों को भी दर्शाया गया है, जिनमें उनके पहनावे और सार्वजनिक उपस्थिति को दिखाया गया है. यह डॉक्यूमेंट्री उनकी राजनयिक गतिविधियों, उनके आसपास मौजूद सीक्रेट सर्विस की गतिविधियों और प्रथम परिवार के सदस्यों के साथ उनकी निजी बातचीत पर भी प्रकाश डालता है, और कभी-कभी राष्ट्रपति के हल्के-फुल्के अंदाज को भी दिखाता है.

ढाका से कराची सीधी उड़ान की तैयारी, भारत ने कहा- एयरस्पेस और सुरक्षा पहलुओं पर रहेगी कड़ी नजर

भारत सरकार ने बांग्लादेश की राष्ट्रीय एयरलाइन बिमान बांग्लादेश द्वारा ढाका से कराची के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने के प्रस्ताव पर संज्ञान लिया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत देखी जा रही हैं। सरकार से यह भी पूछा गया था कि क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी एयरलाइन की ओर से भारतीय एयरस्पेस के इस्तेमाल को लेकर कोई औपचारिक या अनौपचारिक अनुरोध मिला है। इस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों को भारत-बांग्लादेश के बीच वर्ष 1978 में हुए एयर सर्विसेज समझौते के तहत सक्षम प्राधिकरणों द्वारा उचित विचार के बाद निपटाया जाता है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीतिक संवेदनशीलता और पाकिस्तान से जुड़े पिछले द्विपक्षीय अनुभवों को ध्यान में रखते हुए ही ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। सरकार लगातार क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर नजर रखती है ताकि देश के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। एक अन्य सवाल के जवाब में सरकार ने स्वीकार किया कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रणनीतिक रक्षा समझौते की रिपोर्टों पर भी उसकी नजर है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारत सभी क्षेत्रीय साझेदारों के साथ संवाद बनाए रखता है और अपनी सुरक्षा से जुड़े हर पहलू पर आवश्यक कदम उठाता है। इसके अलावा, पाकिस्तान और चीन की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की जा रही टिप्पणियों पर भी सरकार ने अपना रुख दोहराया। मंत्री ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सीधे तौर पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था और 10 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच सीधे संवाद से संघर्षविराम पर सहमति बनी थी।

भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत जारी राज्यसभा में सरकार ने दी जानकारी

सरकार ने राज्यसभा में बताया कि अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और दोनों देश आपसी फायदे वाले समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि दोनों देशों की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के आधार काम करती है। सिंह ने कहा, 'द्विपक्षीय मतभेदों को उच्च-स्तरीय और संस्थागत संवाद के माध्यम से सुलझाया जाता है।' दरअसल विदेश मंत्रालय (MEA) से अमेरिका के साथ रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग पर भारत के वर्तमान रुख और वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति और मतभेद के क्षेत्रों के बारे में पूछा गया था। विदेश मंत्रालय (MEA) से अमेरिका के साथ रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग पर भारत के वर्तमान रुख और वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति और मतभेद के क्षेत्रों के बारे में पूछा गया था। जिस पर विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, 'द्विपक्षीय मतभेदों को उच्च-स्तरीय और संस्थागत संवाद के माध्यम से सुलझाया जाता है।'

विदेश राज्यमंत्री ने कहा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है, जो आतंकवाद रोधी, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, विश्वसनीय प्रौद्योगिकियों, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और एक स्वतंत्र, खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहमति साझा करते हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक साझेदारी और संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे समझौते भी हैं।

जवाब में कहा गया है कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, दोनों पक्ष फरवरी 2025 में शुरू की गई पहल के तहत काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना और विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना है। कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, दिसंबर 2025 तक 3,53,737 भारतीय छात्र अमेरिका में उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं।

संपादक की कलम से

देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर बहस के केंद्र में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा हाल ही में लागू किए गए कुछ नए नियमों पर अदालत द्वारा लगाए गए न्यायिक विराम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह बहस केवल नियमों की वैधता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा शिक्षा में समता, अवसरों की समानता और सामाजिक न्याय जैसे मूलभूत मुद्दों तक फैला हुआ है। सवाल यह है कि क्या ये नियम शिक्षा में सुधार की दिशा में एक कदम हैं या फिर वे अनजाने में नई असमानताओं को जन्म दे रहे हैं?यूजीसी का तर्क है कि नए नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, वैश्विक मानकों के अनुरूप पाठ्यक्रमों का निर्माण और विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता देना है। शिक्षकों की नियुक्ति, प्रोन्नति, शोध मानकों और शैक्षणिक प्रशासन से जुड़े इन नियमों को 'मेरिट' और 'पारदर्शिता' के नाम पर पेश किया गया। आयोग का दावा है कि इससे संस्थानों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा।लेकिन आलोचकों का कहना है कि यही 'मेरिट' की परिभाषा अपने आप में पक्षपाती हो सकती है। भारत जैसे सामाजिक रूप से विविध देश में समान अवसर की अवधारणा केवल समान नियमों से पूरी नहीं होती। सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय असमानताओं को नज़रअंदाज़ कर बनाए गए नियम कमजोर तबकों को और पीछे धकेल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, शोध प्रकाशनों, अंतरराष्ट्रीय जर्नलों या विदेशी अनुभव को अत्यधिक महत्व देना उन शिक्षकों और छात्रों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, जिनके पास संसाधनों की पहले से ही कमी है।यहीं से मामला अदालत तक पहुँचा। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यूजीसी के कुछ नियम संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ जाते हैं। अदालत ने प्रथम दृष्टया इन दलीलों को गंभीर मानते हुए नियमों पर अस्थायी रोक लगाई। यह न्यायिक विराम केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि नीति-निर्माताओं के लिए एक चेतावनी भी है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुधार करते समय जमीनी हकीकत को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। इस पूरे विवाद ने एक बुनियादी सवाल को फिर से सामने ला दिया है—क्या शिक्षा में समता का मतलब सबके लिए एक जैसे नियम हैं, या फिर ऐसी नीतियाँ जो असमान परिस्थितियों में भी समान अवसर सुनिश्चित करें? यदि नियम केवल शहरी, संसाधन-संपन्न और प्रतिष्ठित संस्थानों के अनुकूल हों, तो वे ग्रामीण, पिछड़े और नए विश्वविद्यालयों के लिए बाधा बन सकते हैं। इससे शिक्षा की खाई और चौड़ी होने का खतरा है।

आरोपों के शोर से अलग राजनीति के 'दादा-पुरूष'

यह खबर केवल एक व्यक्ति के निधन की नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के एक पूरे युग के अचानक थम जाने की सूचना है। 28 जनवरी 2026 की सुबह जब बारामती में हुए विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार के असामयिक निधन की पुष्टि हुई, तो वह क्षण केवल पवार परिवार के लिए नहीं, बल्कि समूचे महाराष्ट्र और देश की राजनीति के लिए गहरे शोक और स्तब्धता का कारण बन गया। जिस नेता को लोग अधिकार, अनुभव और निर्णय क्षमता का पर्याय मानते थे, उसका इस तरह अचानक चले जाना सत्ता, प्रशासन और राजनीतिक संतुलन में एक बड़ा रिक्त स्थान छोड़ गया है। एक संभावनाओं भरी महाराष्ट्र की राजनीति एवं राष्ट्रीय विचारों का सफर ठहर गया, उनका निधन न केवल महाराष्ट्र के लिये, भारत की राष्ट्रवादी सोच के लिये बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रवादी राजनीति पर एक गहरा आघात है, अपूरणीय क्षति है। उनके निधन से सहकारी आन्दोलन को भी गहरा धक्का लगा है।अजित पवार का जीवन किसी राजसी विरासत की सहज कहानी नहीं था। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देओली प्रवरा क्षेत्र में जन्मे अजित पवार ने जीवन को बहुत करीब से संघर्ष करते हुए देखा। उनके पिता अनंतराव पवार फिल्म जगत से जुड़े रहे, राजकमल स्टूडियो में काम किया, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां साधारण रहीं। औपचारिक शिक्षा माध्यमिक स्तर तक ही सीमित रही, किंतु जीवन की व्यावहारिक पाठशाला ने उन्हें वह सिखाया जो बड़े-बड़े शैक्षणिक संस्थान भी नहीं सिखा पाते। शायद यही कारण रहा कि अजित पवार की राजनीति किताबों से नहीं, जमीन से निकली हुई राजनीति थी, जिसमें किसानों की पीड़ा, सहकारी संस्थाओं की ताकत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नब्ज साफ दिखाई देती थी। राजनीति में उनका प्रवेश किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि सहकारी आंदोलन की प्रयोगशाला से हुआ। 1982 में मात्र बीस वर्ष की आयु में उन्होंने एक चीनी सहकारी संस्था का चुनाव लड़ा। यह वही दौर था जब महाराष्ट्र की राजनीति में सहकारी संस्थाएं सत्ता की रीढ़ मानी जाती थीं। अजित पवार ने बहुत जल्दी समझ लिया कि यदि ग्रामीण महाराष्ट्र को साधना है तो उसे बैंक, चीनी मिल, सिंचाई और बिजली से जोड़ना होगा। यही समझ आगे चलकर उनकी राजनीतिक पहचान की सबसे बड़ी ताकत बनी। 1991 अजित पवार के राजनीतिक जीवन का निर्णायक वर्ष रहा। पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बनने के साथ ही उन्होंने वित्तीय प्रशासन और संगठन संचालन में अपनी दक्षता का परिचय दिया। सोलह वर्षों तक इस पद पर बने रहना अपने आप में उनकी विश्वसनीयता और पकड़ को दर्शाता है। उसी वर्ष बारामती से लोकसभा के लिए निर्वाचित होना उनके बढ़ते कद का प्रमाण था, लेकिन उन्होंने यह सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए छोड़ दी। यह फैसला केवल पारिवारिक निष्ठा का नहीं, बल्कि

अजित पवार का जीवन किसी राजसी विरासत की सहज कहानी नहीं था। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देओली प्रवरा क्षेत्र में जन्मे अजित पवार ने जीवन को बहुत करीब से संघर्ष करते हुए देखा। उनके पिता अनंतराव पवार फिल्म जगत से जुड़े रहे, राजकमल स्टूडियो में काम किया, लेकिन

राजनीतिक दूरदृष्टि का भी उदाहरण था। इसके बाद विधानसभा में प्रवेश और फिर लगातार बारामती से जीत ने उन्हें जनाधार का वह आधार दिया, जिसे महाराष्ट्र की राजनीति में विरले ही कोई चुनौती दे सका। अजित पवार को सत्ता के गलियारों में पहुंचाने वाली सबसे बड़ी विशेषता उनकी प्रशासनिक पकड़ थी। कृषि, बागवानी, बिजली और जल संसाधन जैसे कठिन और संवेदनशील विभागों को संभालते हुए उन्होंने विकास और विवाद दोनों को नजदीक से जिया। जल संसाधन मंत्री के रूप में कृष्णा घाटी और कोकण सिंचाई परियोजनाओं से उनका नाम जुड़ा। इन परियोजनाओं ने जहां किसानों के लिए पानी और उम्मीद का संदेश दिया, वहीं आलोचनाओं और आरोपों का बोझ भी उनके कंधों पर रखा। इसके बावजूद वे उन नेताओं में रहे जो फाइलों से नहीं, फैसलों से पहचाने जाते थे। उपमुख्यमंत्री के रूप में उनका सफर महाराष्ट्र की राजनीति में एक अनोखा अध्याय है। छह बार इस पद तक पहुंचना केवल राजनीतिक संयोग नहीं था, बल्कि सत्ता संतुलन, गठबंधन राजनीति और संगठनात्मक ताकत का परिणाम था। वे सरकार में अक्सर संकटमोचक की भूमिका में दिखे। बजट, वित्तीय प्रबंधन और संसदीय रणनीति में उनकी पकड़ ऐसी थी कि विरोधी भी उनके अनुभव को नजरअंदाज नहीं कर पाते थे। उन्हें महत्वाकांक्षी कहा गया, कभी-कभी कठोर और रूखे स्वभाव का नेता भी बताया गया, लेकिन यह भी सच है कि सत्ता की वास्तविकता को वे भावनाओं से नहीं, निर्णयों से देखते थे। विवाद उनके राजनीतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे। सिंचाई घोटाले से लेकर बयानबाजी तक, कई मौके ऐसे आए जब उनकी छवि पर प्रश्नचिह्न लगे। "अगर बांध में पानी नहीं है तो क्या पेशाब करके भरें?" जैसे बयान ने उन्हें आलोचनाओं के केंद्र में ला खड़ा किया। उन्होंने माफी भी मांगी, सफाई भी दी और समय के साथ उन विवादों से उबरते हुए फिर सत्ता के शीर्ष पर लौटे। यह उनकी राजनीतिक जिजीविषा का प्रमाण था कि आलोचना और आरोप उन्हें रोक नहीं पाए। शरद पवार के साथ उनके रिश्ते को लेकर भी हमेशा चर्चाएं रहीं। कभी मतभेद, कभी दूरी और कभी सियासी अलग राह की अटकलें। लेकिन अजित पवार स्वयं को हमेशा शरद पवार का अनुयायी बताते रहे। उन्हें मिला "दादा" का संबोधन केवल पारिवारिक नहीं था, बल्कि वह एक राजनीतिक ब्रांड बन चुका था, जो उनके समर्थकों में भरोसे और नेतृत्व की भावना जगाता था। वे संगठनकर्ता भी थे और प्रशासक भी, रणनीतिकार भी और जमीनी नेता भी। उन्हें अपनी विविध आयामी भूमिकाओं से अपने को मिले 'दादा' के अलंकरण को सार्थक भी किया और जीवंतता भी दी। उनका असामयिक निधन एक क्रूर विडंबना है। जिस नेता ने दशकों तक सत्ता की उड़ान भरी, उसकी जीवन यात्रा एक विमान हादसे में थम गई। कहा जाता है कि दुर्घटना से कुछ समय पहले तक वे पूरी तरह सक्रिय थे, योजनाओं, बैठकों और राजनीतिक समीकरणों में व्यस्त। यह अचानक आई मृत्यु उस अनिश्चितता को रेखांकित करती है, जो सत्ता और जीवन दोनों के साथ जुड़ी है।

दुनिया जल के वैश्विक दिवालियापन की ओर बढ़ रही है

"जल है तो जीवन है"-यह पंक्ति कोई नारा भर नहीं, बल्कि मानव सभ्यता का शाश्वत सत्य है। बिना जल के जीवन की कल्पना भी संभव नहीं। किंतु विडंबना यह है कि जिस जल को हम जीवन का आधार मानते हैं, वही आज सबसे अधिक संकटग्रस्त संसाधन बन चुका है। देश-दुनिया में जल संकट के हालात विकराल हो चुके हैं और यह संकट अब केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानवीय लापरवाही, भ्रष्टाचार और मूल्यहीन शासन का भी परिणाम बनता जा रहा है। विश्व स्तर पर लगभग 25 देश अत्यधिक जल तनाव से जूझ रहे हैं। चार अरब से अधिक लोग वर्ष में कम से कम एक माह पानी की गंभीर कमी का सामना करते हैं। मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्र इस संकट की अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहां 60 करोड़ से अधिक लोग उच्च जल तनाव वाले क्षेत्रों में रहते हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्य सबसे अधिक प्रभावित हैं, जबकि चेन्नई, बेंगलूरु और दिल्ली जैसे महानगरों में पानी की कमी रोजमर्रा की समस्या बन चुकी है। दरअसल, जल संकट अब 'वाटर स्ट्रेस' से आगे बढ़कर 'ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी' यानी दुनिया जल के वैश्विक दिवालियेपन की ओर बढ़ रही है। स्थिति यह है कि जल स्रोतों का दोहन इतनी तीव्रता से हो रहा है कि

उनकी प्राकृतिक भरपाई असंभव होती जा रही है। भूजल स्तर निरंतर गिर रहा है, नदियां सूख रही हैं और तालाब अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहे हैं। यह संकट केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक संकट भी है। जल संकट का सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। कृषि, उद्योग और ऊर्जा-तीनों ही क्षेत्र पानी पर निर्भर हैं। जब खेतों को पानी नहीं मिलता, उद्योग ठप होते हैं और बिजली उत्पादन प्रभावित होता है, तो देश की जीडीपी में 6 प्रतिशत तक की कमी का खतरा उत्पन्न हो जाता है। आमजन के लिए यह संकट जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन जाता है। जहां पानी पर्याप्त है, वहां बर्बादी हो रही है और जहां पानी की सबसे अधिक आवश्यकता है, वहां लोग बूंद-बूंद को तरस रहे हैं। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय बनाया है। जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे कार्यक्रम इसी दिशा में ऐतिहासिक पहल हैं। जल जीवन मिशन का लक्ष्य हर घर तक नल से जल पहुंचाना है, ताकि स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित किया जा सके। अटल भूजल योजना भूजल के सतत प्रबंधन और सामुदायिक सहभागिता पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना "हर खेत को पानी" के संकल्प को साकार करने का प्रयास है। इसके साथ ही जल शक्ति अभियान के तहत वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और जनभागीदारी पर विशेष जोर दिया गया। इन योजनाओं ने निश्चित रूप से जल संरक्षण के प्रति राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत किया है। कई क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनी हैं, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा मिला है और भूजल पुनर्भरण के प्रयास

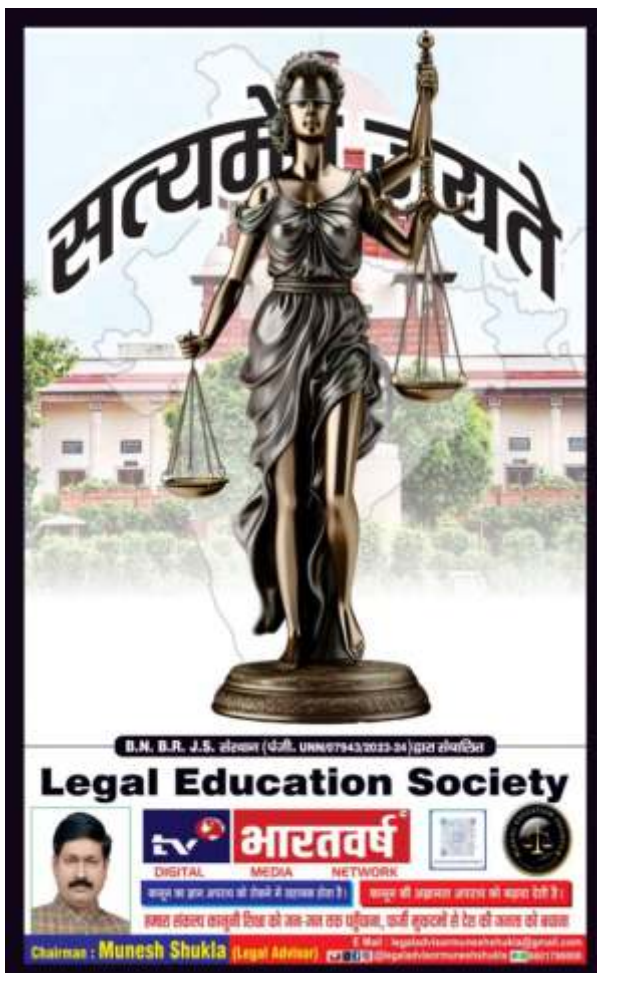

कॉर्पोरेट राजनीति और नैतिक

नेतृत्व पर आधारित पुस्तक का विमोचन

कॉपोरेट राजनीति, करियर और नैतिक नेतृत्व पर केंद्रित पुस्तक ने पेश किया समकालीन कार्यस्थलों का यथार्थ महाराष्ट्र के तुमसर शहर स्थित श्री संत रविदास सार्वजनिक वाचनालय, तुमसर के कार्यालय में आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर पुस्तक "Breaking...

कॉपोरेट राजनीति, करियर और नैतिक नेतृत्व पर केंद्रित पुस्तक ने पेश किया समकालीन कार्यस्थलों का यथार्थ महाराष्ट्र के तुमसर शहर स्थित श्री संत रविदास सार्वजनिक वाचनालय, तुमसर के कार्यालय में आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर पुस्तक "Breaking Politics - Empowering Experts" का भव्य प्रकाशन समारोह मान्यवर अतिथियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह पुस्तक वैभव देशपांडे और रोशन भोंडेकर द्वारा सह-लेखित है। कार्यक्रम के दौरान लेखक रोशन भोंडेकर के माता-पिता श्री दिलीप भोंडेकर एवं श्रीमती सुधा भोंडेकर ने क्षेत्र के अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ मिलकर पुस्तक का विधिवत लोकार्पण किया। तेजी से विस्तार कर रहे भारत के कॉर्पोरेट और तकनीकी परिदृश्य में करियर केवल कौशल और प्रदर्शन से ही नहीं, बल्कि संगठनों के भीतर मौजूद अदृश्य शक्ति संरचनाओं से भी प्रभावित हो रहे हैं। पदोन्नति, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और नेतृत्व की दृश्यता अक्सर आंतरिक समीकरणों पर निर्भर होती जा रही है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच कॉर्पोरेट राजनीति आज पेशेव नीति निर्माताओं और उद्योग जगत में चर्चा का विषय बन चुकी है।

भारत का प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र पांच मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। हालिया उद्योग सर्वेक्षणों के अनुसार, तकनीकी कौशल के साथ-साथ कार्यस्थल संस्कृति और आंतरिक राजनीति कर्मचारी असंतोष और इस्तीफों के प्रमुख कारण बन रहे हैं। 2024 की एक रिपोर्ट में लगभग 48 प्रतिशत मध्य-स्तरीय आईटी पेशेवरों ने पदोन्नति में पारदर्शिता की कमी और पक्षपात को करियर बदलने की वजह बताया।

इसी पृष्ठभूमि में राजमंगल पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित यह गैर-काल्पनिक पुस्तक सामने आई है। Breaking Politics - Empowering Experts शोध और अनुभव आधारित दृष्टिकोण से यह विश्लेषण करती है कि किस प्रकार छिपे हुए सत्ता खेल नौकरियों और करियर को प्रभावित करते हैं और पेशेवर इन परिस्थितियों में नैतिकता बनाए रखते हुए प्रभावी कैसे रह सकते हैं। पुस्तक में कॉर्पोरेट राजनीति को स्वस्थ संवाद नहीं, बल्कि छिपे एजेंडे, हेरफेर और सत्ता संघर्ष के रूप में परिभाषित किया गया है। लेखकों ने बताया है कि ये तत्व नवाचार, मनोबल और दीर्घकालिक संगठनात्मक प्रदर्शन को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही, समाधान के रूप में व्यावहारिक रणनीतियां प्रस्तुत की गई हैं, जैसे योगदान का दस्तावेजीकरण, संगठनात्मक प्राथमिकताओं के साथ कार्यों का संरेखण और नेतृत्व की जवाबदेही।

हॉकी इंडिया ने पुरुष प्रो लीग से पहले 33 सदस्यीय संभावित कोर ग्रुप की घोषणा की

हॉकी इंडिया ने गुरुवार को एक से सात फरवरी तक ओडिशा के राउरकेला में आयोजित होने वाले सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के लिए 33-सदस्यीय संभावित कोर ग्रुप की घोषणा कर दी है। यह शिविर 10 से 15 फरवरी तक बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में होने वाली एफआईएच पुरुष प्रो लीग के आगामी चरण के लिए टीम की तैयारियों का हिस्सा हैं। घरेलू चरण से भारत साल के पहले अभियान की शुरुआत करेगा। यह टीम हाल ही में समाप्त हुई हीरो हॉकी इंडिया लीग के बाद इकट्ठा हो रही है, जिसने कई सीनियर खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी अनुभव दिया, साथ ही युवा खिलाड़ियों को कुछ बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका भी दिया। इस शिविर में पवन, सूरज करकेरा, मोहित होन्नेनहल्ली शशिकुमार और प्रिंसदीप सिंह गोलकीपर के तौर पर शामिल होंगे। वहीं, रक्षापंक्ति में अमित रोहिदास, जरमनप्रीत सिंह, संजय, हरमनप्रीत सिंह, जुगराज सिंह, सुमित, पूवन्ना चंदुरा बॉबी, यशदीप सिवाच, नीलम संजीव ज़ेस और अमनदीप लाकरा शामिल हैं।

कार खरीदारों को बड़ा झटका, Citroen की ये गाड़ियां हुई महंगी, जानें नई कीमतें

महंगे हुए मॉडल्स की डिटेल्स इस प्रकार है

1. सिट्रोएन C3: इसकी नई कीमत अब 4.95 लाख रुपये से लेकर 9.45 लाख रुपये तक हो गई है। खास बात यह है कि कंपनी ने इसके Live (O) मैनुअल वर्जन की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। 2. सिट्रोएन बेसाल्ट (Basalt): इस कूपे एसयूवी के सभी वेरिएंट्स (You, Plus और Max) में एक समान 20,000 रुपये की वृद्धि की गई है। अब इसकी टॉप रेंज 13.35 लाख रुपये तक पहुँच गई है। 3. सिट्रोएन एयरक्रॉस (Aircross): इसकी कीमतों में वेरिएंट के हिसाब से भारी अंतर आया है। पांच सीटों वाले Max Turbo वेरिएंट की कीमत को स्थिर रखा गया है, जो ग्राहकों के लिए थोड़ी राहत की खबर है।

मनप्रीत सिंह समेत तीन प्लेयर्स पर बड़ी कार्रवाई, प्रो लीग के संभावित खिलाड़ियों की सूची से किया बाहर

भारतीय पुरूष हॉकी टीम के अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह समेत तीन खिलाड़ियों को प्रो लीग के आगामी सत्र से पहले संभावित खिलाड़ियों की सूची से बाहर के फैसला पर भले ही कइयों को हैरानी हुई हो लेकिन सूत्रों के अनुसार यह फैसला पिछले साल दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर ही 'अनुशासनात्मक' कारणों से ले लिया गया था। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि किसी भारतीय खिलाड़ी के सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों का हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप टिर्की के (412) रिकॉर्ड की बराबरी से रोकने के लिए मनप्रीत को बाहर किया गया है। मनप्रीत इस रिकॉर्ड से एक मैच दूर हैं। टीम के करीबी सूत्रों ने हालांकि बताया कि मनप्रीत सिंह, दिलप्रीत सिंह और गोलकीपर कृशन बहादुर पाठक को बाहर करने का फैसला पिछले साल दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर ही ले लिया गया था। भारतीय टीम ने दक्षिण

अफ्रीका में सात से दस दिसंबर 2025 के बीच दो टेस्ट और एक नुमाइशी मैच खेले थे। सूत्रों ने कहा, 'दक्षिण अफ्रीका दौरे पर अनुशासनहीनता का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया था जब एक खिलाड़ी टीम बैठक से गायब था और बाद में पता चला कि उसे मनप्रीत, दिलप्रीत और पाठक ने कथित तौर पर प्रतिबंधित पदार्थ वाली च्युइंग गम खिलाई थी जिससे वह बेहोश हो गया और पूरी रात उसे संभालना पड़ा। अगली सुबह वह टीम बैठक में भी नहीं जा सका।'

ओलंपिक 2036 दावेदारी : एक्वाटिक्स, नौकायन, साइकिलिंग पर रहेगा जोर

भारत की ओलंपिक 2036 की दावेदारी मजबूत करने के लिये पदक रणनीति में भी बदलाव किये जा रहे हैं ताकि एक्वाटिक्स और साइकिलिंग जैसे खेलों में भी मजबूती से उपस्थिति दर्ज कराई जा सके जिनमें आम तौर पर प्रदर्शन औसत रहता है। इन दोनों खेलों में सौ से अधिक ओलंपिक पदक दाव पर लगे होते हैं लेकिन भारत की झोली खाली ही रहती है। खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने पीटीआई से कहा, 'अगर हमारे देश में ओलंपिक होते हैं और हमारे खिलाड़ी छह पदक लेकर 71वें स्थान पर रहते हैं तो क्या यह अच्छा लगेगा, जैसा पेरिस (2024) में हुआ था। हमें इस पर तुरंत गौर करना होगा।' सूत्र ने कहा, 'मेजबान देश ओलंपिक में अपना प्रदर्शन बेहतर करने पर जोर देते हैं ताकि अपने देश में होने वाले खेलों में मैदान पर भी उनका परचम लहराए।' चीन ने 2008 बीजिंग ओलंपिक से ऐसे खेलों में अपने प्रदर्शन में सुधार किया जिसमें अतीत में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। इनमें मुक्केबाजी, केनोइंग और तीरंदाजी शामिल है। सूत्र ने कहा, 'भारत अपने खेलों के सफर में एक अहम मोड़ पर है और चुनौती यह पक्का करना है कि हम यहां से ऊपर उठें, नीचे न गिरे। बुनियादी ढांचा चिंता का विषय नहीं है, यह सबसे आसान काम है और शायद सबसे अधिक दिखने वाला भी, इसीलिए इसके प्रति जुनून है। बड़ी चिंता एक खेल देश के रूप में हमारे दर्जे की है।' इसलिए अब फोकस स्कूलों पर होगा जहां से 2036 ओलंपिक के भावी सितारे निकलेंगे।

कौन जीतेगा टी20 विश्व कप 2026 का खिताब? रवि शास्त्री ने कर दी भविष्यवाणी

टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री का मानना है कि मौजूदा चैंपियन भारत इस बार इतिहास रच सकता है और लगातार दो बार खिताब जीतने वाली पहली टीम बन सकता है। भारतीय टीम का मौजूदा प्रदर्शन बेहद जबरदस्त रहा है। 2024 में टी20 विश्व कप का खिताब जीतने के बाद से टीम इंडिया ने कोई भी द्विपक्षीय सीरीज या टूर्नामेंट नहीं गंवाया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत का जीत-हार का रिकॉर्ड 32-5 का है, जो किसी भी विरोधी टीम के लिए खतरे की घंटी है। टी20 रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज भारतीय टीम के पास इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन दल है। टीम में नंबर 1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और नंबर 1 टी20 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती शामिल हैं, जो विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं। शास्त्री ने टीम की मजबूती पर बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि डिफेंडिंग चैंपियंस स्पष्ट रूप से जीत के प्रबल दावेदार

के तौर पर शुरुआत करेंगे। अगर आप एक-एक खिलाड़ी को देखें, उनकी मौजूदा फॉर्म, मैच फिटनेस और हाल के दिनों में उन्होंने जितना क्रिकेट खेला है, यह सब उन्हें साफ तौर पर फेवरेट बनाता है। खास तौर पर जब आप उनके टॉप ऑर्डर और उनकी मौजूदा फॉर्म को देखते हैं, तो स्थिति और भी मजबूत नजर आती है।' टी20 विश्व कप की तैयारी में 'मेन इन ब्लू' का सफर अब तक लगभग बेदाग रहा है।

सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

गैंडे से भिड़ गया नन्हा हिरण

इस महीने की शुरुआत में पोलैंड के एक चिड़ियाघर से एक मजेदार वीडियो सामने आया है. इसे काफी लोग शेयर कर रहे हैं.

यह वीडियो एक नन्हें हिरण और विशालकाय गैंडे की लड़ाई का है, जिसे लोग खूब शेयर कर रहे हैं और इंटरनेट पर ये जोड़ी छाया हुआ है. रॉयटर्स के मुताबिक, इस महीने पोलैंड के एक चिड़ियाघर में एक ज़बरदस्त लड़ाई हुई. इसका वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल है. जब एक छोटा सा मुंटजैक हिरण एक विशाल गैंडे से भिड़ गया. ऐसा लगा कि वह जीत गया. 'मुंटजैक डैड' नाम का 17 किलो का हिरण 1660 किलो की माऊसिया (गैंडे) को घूरते हुए बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था. यह वीडियो व्रोकला चिड़ियाघर में फिल्माया गया था.

सुरक्षा और अव्यवस्था को लेकर उठे सवाल

भारतीय ने दिखाई यूरोप की असलियत

यूरोप लंबे समय से दुनियाभर के यात्रियों का ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है. फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की चमक-दमक फिल्मों और सोशल मीडिया रील्स में कुछ ऐसी दिखाई जाती है कि लोग वहां जाने का सपना संजो लेते हैं, लेकिन हाल ही में एक वीडियो ने यूरोप की उस तस्वीर पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो आमतौर पर इंटरनेट पर दिखाई जाती है. भारतीय ट्रैवल व्लॉगर प्रतीक सिंह ने अपने वायरल वीडियो में यूरोप का एक अलग ही चेहरा दिखाया है. वीडियो में कई यूरोपीय शहरों की सड़कों पर फैली गंदगी साफ नजर आती है. प्रतीक का कहना है कि सोशल मीडिया रील्स में जो यूरोप दिखाया जाता है, हकीकत उससे काफी अलग है. प्रतीक सिंह वीडियो में बताते हैं कि यूरोप घूमने के लिए शेंगेन वीजा लेना आसान नहीं है. इसके लिए छह महीने के बैंक स्टेटमेंट, तीन महीने के ITR, ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स और महंगे फ्लाइट टिकट्स की जरूरत पड़ती है. इसके बावजूद, उनके मुताबिक, वहां पहुंचने पर कई जगहों पर गंदगी, अव्यवस्था और अपराध देखने को मिलते हैं. वीडियो में वह कहते हैं कि 10 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करके आप यूरोप यही देखने आते हैं? ये सब तो भारत में भी देखा जा सकता है. प्रतीक ने अपने वीडियो में यह भी दावा किया कि आज के समय में जापान, चीन, ताइवान, साउथ कोरिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे पूर्वी देश टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में आगे निकल चुके हैं.

व्लॉगर ने यूरोप का दिखाया नजारा, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए (Photo:Insta/@travelwprateek)

अंडरवियर के रंग से तय होगा भविष्य!

दुनिया भर में अजीब-ओ-गरीब ट्रेंड्स की कोई कमी नहीं है. गुड लक के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते. कभी टोटके, कभी रंग, तो कभी छोटी-छोटी मान्यताएं. ऐसा ही एक दिलचस्प ट्रेंड एक बार फिर चर्चा में है, जो नए साल की रात से जुड़ा है.जब 31 दिसंबर की रात घड़ी बारह बजाती है और नया साल दस्तक देता है, तो दुनिया के कई हिस्सों में लोग एक खास परंपरा निभाते हैं. न्यू ईयर की रात खास रंग का अंडरवियर पहनना. मान्यता है कि जिस रंग का अंडरवियर आप पहनते हैं, वही तय करता है कि आने वाले साल में आपकी किस्मत, प्यार और पैसा किस दिशा में जाएगा. यह परंपरा लैटिन अमेरिका से लेकर यूरोप तक पुरानी मानी जाती है.

बेंगलुरु में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर टांगी महिला की तस्वीर

'नज़र' से बचाने का अनोखा हथकंडा

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीबो-गरीब तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. साड़ी पहने, बड़ी-बड़ी आंखों वाली एक महिला की सेल्फी अलग-अलग जगहों पर टंगी नजर आ रही है. वायरल पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक के कई अंडर-कंस्ट्रक्शन साइट्स पर यह तस्वीर लगाई गई है.

इसी वजह से लोगों के मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आखिर यह महिला कौन है, उसकी तस्वीर हर जगह क्यों दिखाई दे रही है और इसके पीछे की असली वजह क्या है. यही सवाल इस तस्वीर को और रहस्यमय बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसे चर्चा का विषय बना चुके हैं. यह मामला तब सुर्खियों में आया, जब यूनिटेकी नाम के एक X यूजर ने 5 जनवरी को इस तस्वीर को पोस्ट किया. यूजर ने लिखा कि उन्होंने कर्नाटक में कई जगह यह फोटो देखी, लेकिन जब इसके बारे में गूगल पर जानकारी ढूंढने की कोशिश की, तो कुछ भी हाथ नहीं लगा. इसके बाद पोस्ट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं और देखते-ही-देखते यह चर्चा फैल गई. पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने बताया कि उन्होंने भी यही तस्वीर अलग-अलग इमारतों और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर देखी है. कुछ लोगों ने अपने इलाकों की तस्वीरें शेयर कर यह जताने की.

यह पहली बार नहीं है जब यह तस्वीर चर्चा में आई हो (Photo:X/@unitechy)

क्राइम, सस्पेंस और ट्रॉमा की गहराई में उतरती भूमि पेडनेकर

बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर की क्राइम थ्रिलर सीरीज दलदल आज ओटीटी प्लेटफार्म प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है। सीरीज के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच सीरीज को लेकर चर्चा थी। ट्रेलर में दिखाए गए क्राइम, सस्पेंस और खूंखार सीन से दर्शकों का उत्साह और बढ़ गया। आइए आज आपको बताते हैं क्या क्राइम थ्रिलर पसंद आने वालों के लिए ये सीरीज बिंज वॉच साबित होगी। क्या ये सीरीज आपके वीकेंड को मजेदार बनाएगी। ऐसे वक्त में केस की कमान संभालती हैं डीसीपी रीता फरेरा (भूमि पेडनेकर)। रीता एक सख़्त और समझदार अफसर हैं, लेकिन उनकी लड़ाई सिर्फ अपराध से नहीं है। उनके भीतर भी एक जंग चल रही है बीते हुए कल की, जो आज भी उन्हें चैन से जीने नहीं देता। रीता का बचपन दर्द और टूटन से भरा रहा है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, रीता को एहसास होता है कि ये केस जितना बाहर दिखाई देता है, उससे कहीं ज़्यादा अंदर तक जुड़ा हुआ है। कातिल की सोच और उसकी अपनी मानसिक हालत के बीच एक अजीब-सी समानता नज़र आने लगती है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि कातिल कौन है सवाल ये है कि रीता इस उलझन से बाहर कैसे निकलेगी? सीरीज में भूमि पेडनेकर पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आ रही हैं जो अपने रोल में काफी प्रभावशाली लग रही हैं। भूमि अपने हर नए किरदार के साथ दर्शकों को चौंका देती हैं। दीपक तिजोरी की बेटी समारा तिजोरी कुछ दृश्यों में बढ़िया लगती हैं, वहीं कुछ जगह उनका अभिनय थोड़ा कमजोर महसूस होता है। परेश रावल के बेटे आदित्य रावल का किरदार उन्होंने पूरी मजबूती के साथ निभाया है। चिनमय भी अपने रोल में सटीक हैं गीता अग्रवाल ने अपने किरदार को सहजता से निभाया है। अन्य सपोर्टिंग कलाकारों जैसे अनंत महादेवन, राहुल भट्ट, सौरभ गोयल और विजय कृष्णा के किरदार भी बढ़िया लग रहे हैं। अमृत राज गुप्ता द्वारा निर्देशित वेब सीरीज़ 'दलदल' दर्शकों को पूरी कहानी के दौरान जोड़े रखने की कोशिश करती है। ज़्यादातर हिस्सों में यह कोशिश सफल रहती है और निर्देशन की पकड़ साफ़ नज़र आती है। हालांकि कुछ दृश्यों में पात्रों के बीच कहानी को ज़रूरत से ज़्यादा खींचा गया है, जिसे थोड़ा कम किया जा सकता था। इसके बावजूद, अधिकांश एपिसोड में निर्देशन प्रभावशाली है और कहानी में आए मोड़ दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखते हैं।

यूपी में इन 3 कारणों की वजह से क्या टल जाएंगे पंचायत चुनाव?

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टलने की खबरों के बीच पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है. सोशल मीडिया पर चर्चा है कि शंकराचार्य विवाद और यूजीसी नियमों पर उपजी नाराजगी के कारण चुनाव टल सकते हैं. लेकिन इस बीच ओपी राजभर का ने बड़ा बयान दिया है.

उत्तर प्रदेश के गांवों में इन दिनों एक ही चर्चा आम है कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे? बीते कुछ दिनों से राज्य के राजनीतिक हालात और प्रशासनिक व्यस्तता को देखते हुए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव आगे बढ़ सकते हैं. शंकराचार्य विवाद, यूजीसी के नए नियमों पर उपजी नाराजगी और प्रशासनिक व्यस्तता ने इन अफवाहों को हवा दी है. लेकिन यूपी के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे और तैयारियां पूरी की जा रही हैं.

सोशल मीडिया पर चुनाव टलने की खबरों के पीछे तीन मुख्य कारण बताए जा रहे हैं. पहला ये कि प्रयागराज में शंकराचार्य और प्रशासन के बीच हुए विवाद के बाद कई अधिकारियों की नाराजगी और इस्तीफे की खबरों ने सरकार की मशीनरी पर दबाव बनाया है. दूसरा यूजीसी (UGC) के नए नियमों को लेकर 'अपर कास्ट' वोटरों में दिख रही नाराजगी से सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है. चर्चा है कि इस माहौल में सरकार चुनाव का जोखिम नहीं लेना चाहती. वहीं तीसरी ये कि फरवरी का महीना शुरू होने वाला है. लेकिन अभी तक सरकार के भीतर उस स्तर की सक्रियता नहीं दिख रही है जैसी पंचायत चुनाव से पहले होती है. इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस विषय पर चर्चा की है. राजभर के मुताबिक फिलहाल अधिकारी और कर्मचारी SIR जैसे कुछ जरूरी कामों में बिजी चल रहे हैं. जैसे ही वे खाली होंगे वैसे ही चुनाव प्रक्रिया में तेजी आएगी. चुनाव समय पर ही संपन्न कराए जाएंगे. ओपी राजभर ने मीडिया द्वारा बनाए जा रहे माहौल को खारिज करते हुए साफ किया कि अप्रैल से जुलाई के बीच चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है. पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा पेंच आरक्षण सूची को लेकर फंसता है. अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन सी सीट एससी-एसटी (SC-ST) के लिए आरक्षित होगी,कहां ओबीसी उम्मीदवार होंगे और कौन सी सीट सामान्य रहेगी. इसी सूची के आधार पर तय होगा कि पुराने धुरंधर मैदान में उतर पाएंगे या नहीं. लोग अपनी-अपनी सीटों को मैनेज करने की जुगत में भी लगे हैं.

यूजीसी नियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सपा सांसद राजीव राय का आया रिएक्शन

यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन नियमों की भाषा और मंशा पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ये नियम अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जबकि अगली सुनवाई मार्च महीने में होगी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि 2012 के दिशानिर्देश फिलहाल लागू रहेंगे और आगे भी प्रभावी माने जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी सवाल उठाया कि 75 वर्षों में देश ने जाति-विहीन समाज की दिशा में जो प्रगति की है, क्या ऐसे नियम उस प्रक्रिया को पीछे ले जाने वाले साबित हो सकते हैं। अदालत ने कहा कि भारत की एकता और सामाजिक समरसता की झलक शैक्षणिक संस्थानों में दिखाई देनी चाहिए और प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए प्रभावी तंत्र होना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये नियम लाए गए थे, उस समय वे संयुक्त राष्ट्र में थे और अब उन्हें पूरे मामले की जानकारी मिली है।

यूपी में आज हुए चुनाव तो क्या खुल जाएगा BSP का खाता? ऐसा रह सकता है मायावती की पार्टी का हाल

2024 के लोकसभा चुनाव में जहां सपा-कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने जीत का परचम लहराया था, वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) के लिए नतीजे किसी बुरे सपने से कम नहीं थे. दशकों तक यूपी की सत्ता की धुरी रही बसपा का खाता तक नहीं खुला था. इस बीच इंडिया टुडे और C-वोटर के 'मूड ऑफ द नेशन' (जनवरी 2026) के ताजा सर्वे ने एक बार फिर यूपी की सियासी नब्ज टटोली है. क्या शून्य पर सिमटने वाली बसपा ने अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए कोई खास तैयारी की है? क्या मायावती का कोर वोट बैंक आज भी उनके साथ मजबूती से खड़ा है, या वो बीजेपी और सपा की ओर शिफ्ट हो चुका है? आइए, इस रिपोर्ट में देखते हैं कि ताजा आंकड़ों में बसपा कहां खड़ी है. मालूम हो कि लोकसभा चुनाव 2019 में 10 सीटें जीतने वाली बसपा का 2024 के लोकसभा चुनाव में खाता नहीं खुला था. वहीं, मूड ऑफ द नेशन

के लेटेस्ट सर्वे में भी बसपा को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है. सर्वे में बसपा को 5% वोट शेयर तो मिलने का अनुमान है. MOTN सर्वे के अनुसार, अगर आज यूपी में लोकसभा चुनाव हो MOTN सर्वे के अनुसार, अगर आज यूपी में लोकसभा चुनाव होते हैं तो NDA को 47 से 49 मिल सकती हैं. इसके मुकाबले इंडिया अलाइंस (सपा और कांग्रेस) को 30 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है. MOTN सर्वे के आकड़े बताते हैं कि यूपी में अगर आज चुनाव होते हैं तो 44 सीटों के साथ भाजपा NDA की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है. दूसरी तरफ भाजपा के साथी अपना दल (एस) और राष्ट्रीय लोकदल के खाते में भी 4 सीटें जाने का अनुमान है. अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल हैं

पास में कई बच्चों को खड़ा कर यूजीसी नियमों को लेकर अपनी ही सरकार पर भड़कते नजर आए

यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है. सामान्य वर्ग के छात्र और संगठन इन नियमों के विरोध में उतर चुके हैं. इसी बीच भाजपा के पूर्व सांसद और बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी नियमों को लेकर अब खुलकर अपनी बात रखी है.बृजभूषण शरण सिंह ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक वीडियो पोस्ट की है. ये वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है. इस वीडियो में बृजभूषण शरण सिंह के बराबर में कई बच्चे भी खड़े हैं. वीडियो में दिख रहे इन बच्चों का उदाहरण देकर बृजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया है. उन्होंने साफ कहा है कि अगर इन नियमों को वापस नहीं लिया जाएगा तो सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. बृजभूषण शरण सिंह ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक वीडियो पोस्ट की है. ये वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है.

सामानों की डिलीवरी को लेकर दो पक्षों में विवाद, बम से किया हमला, मचा हड़कंप, क्या कहते हैं डीसीपी पश्चिम?

कानपुर में सामान की डिलीवरी को लेकर दो डिलीवरी करने वाले लड़कों के बीच लड़ाई हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष में अपने साथी को बुला लिया, जिसने बम से हमला बोल दिया। बम के हमले से डिलीवरी बॉय घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज का निरीक्षण किया जा रहा है। अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है।

योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के 15 लाख शिक्षकों को सरकारी व निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज सुविधा मिली

प्रदेश सरकार ने शिक्षा जगत से जुड़े लाखों कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक अहम निर्णय लेते हुए राज्य के माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिवारों को सरकारी ही नहीं, बल्कि निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा देने का फैसला किया गया है। इस योजना का लाभ प्रदेश के लगभग 15 लाख शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मी उठा सकेंगे।

यह घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले वर्ष शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर की थी, जिस पर अब मंत्रिपरिषद ने औपचारिक मुहर लगा दी है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर कुल 448 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय अनुमानित है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कुल 32 प्रस्ताव

प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 30 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक रहा। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से शिक्षकों को इलाज के दौरान आर्थिक चिंता से मुक्ति मिलेगी और वे मानसिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि इस फैसले के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों को योजना में शामिल किया गया है। इनमें शामिल हैं.

आयकर विभाग के सर्वे में सनसनीखेज खुलासा, कानपुर रजिस्ट्री ऑफिस में 3500 करोड़ का घोटाला

कानपुर रजिस्ट्री विभाग एक बार फिर आयकर विभाग की कार्रवाई की जद में आया है। गुरुवार को विभाग के जोन-3 में आयकर विभाग ने सर्वे किया। सिविल लाइंस स्थित कार्यालय में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। छह घंटे की जांच में लगभग 3500 करोड़ की विसंगतियों के साक्ष्य मिले हैं। आयकर विभाग को लगभग 800 करोड़ के टैक्स का चूना लगा है। फिलहाल रजिस्ट्री अधिकारियों को दस दिन का समय देकर कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है। आयकर निदेशक के निर्देश पर रजिस्ट्री कार्यालय के जोन वन में सहायक निदेशक विमलेश राय की अगुवाई में अचल संपत्ति की रजिस्ट्री की जांच के लिए सर्वे किया गया। टीम में आयकर निरीक्षक कुलदीप गुप्ता, देव अनंत श्रीवास्तव, कय्यूम अहमद, रवि पासवान के साथ भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। आयकर अधिकारियों ने वर्ष 2020 से 2025 तक की रजिस्ट्री की जांच की। सर्वे टीम का कहना है कि अब तक जिन दस्तावेजों की छानबीन हुई है, उसके अनुसार 3500 करोड़ रुपये की विसंगतियां मिली हैं। आयकर सर्वे के दौरान कई रजिस्ट्री में मनमर्जी पैन लिखा गया। लगभग एक हजार पैन में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी मिलीं। गलत मोबाइल नंबर तक लिखे गए। सर्वे टीम का आकलन है कि ऐसा जानबूझकर किया गया। इसकी आड़ में आयकर विभाग की आंखों में धूल झोंकने का पूरा प्रयास किया गया। रजिस्ट्री विभाग की ओर से संपत्तियों की रजिस्ट्री का जो डाटा आयकर विभाग को भेजा गया, वह वास्तविक रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा था। आयकर विभाग ने वित्तीय गड़बड़ियों और टैक्स चोरी की आशंका के चलते गुरुवार को प्रमुख नमकीन कारोबारी के ठिकानों पर सर्वे की कार्रवाई की।

कानपुर और कानपुर देहात के कुल पांच स्थानों पर आयकर अधिकारियों ने एक साथ धावा बोला। दोपहर से शुरू हुई यह कार्रवाई देर रात तक चलती रही। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। सूत्रों के अनुसार, आयकर विभाग की यह कार्रवाई कारोबारी की कानपुर देहात के रनियां क्षेत्र में स्थित फैक्टरी के अलावा कानपुर के शास्त्री नगर और दादानगर सहित अन्य ठिकानों पर की गई। सर्वे के दौरान करीब 50 से अधिक आयकर अधिकारियों की टीम मौके पर तैनात रही। अधिकारियों ने सभी परिसरों में मौजूद व्यावसायिक रिकॉर्ड, लेखा-बही और डिजिटल डेटा की गहन जांच की।

आईएएस की ट्रेनिंग में हूं, नीली बत्ती की गाड़ी में घुमाऊंगा...फर्जी डीएम ने लड़की को ठगा

यूपी के कानपुर में कल्याणपुर की युवती को झांसा देकर शारीरिक और आर्थिक शोषण करने वाले फर्जी डीएम को पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया है। पुलिस ने बुधवार रात चकेरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। युवती ने आरोप लगाया था कि उसने डीएम बन साढ़े 26 लाख कैश और लाखों के गहने ठग लिए थे। फोन करने पर कहता था आईएएस की ट्रेनिंग में हूं। लौटकर तुम्हें नीली बत्ती वाली गाड़ी में घुमाऊंगा। कई दिन बाद भी जब रुपये नहीं दिए तो 16 जनवरी को युवक, उसके भाई और दोस्त पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कल्याणपुर की युवती की 2023 में चचेरे भाई की शादी में चकेरी निवासी नितेश पांडे से मुलाकात हुई थी। तब नितेश ने खुद को बैंक का फील्ड अफसर बता युवती से करीबी बना ली। इसके बाद युवती को बताया वह महोबा का एसडीएम बन गया है। कुछ दिन बाद आईएएस की परीक्षा पास करने और कानपुर का डीएम बनने की बात कही। कानपुर डीएम का फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भी व्हाट्सएप पर भेजा। इसी झांसे में लेकर रुपये और गहने हड़प लिए। रकम वापस मांगने पर कहता था वह ट्रेनिंग में है। अंत में युवती ने कल्याणपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने बुधवार रात नितेश पांडे को दबोचा।

काशी के रंगधर्मियों ने प्रयागराज में जमाया रंग

नगर की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं साहित्यिक संस्था कामायनी के कलाकारों ने उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक परिषद के आह्वान पर प्रयागराज माघ मेला के मुक्ताकाशी मंच पर पौराणिक कथानक पर आधारित नाटक का अद्भुत मंचन किया। 'अश्वत्थामा हतो, नरो वा, कुंजरो वा' के मंचन ने दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। प्रो. श्याम मोहन अस्थाना द्वारा लिखित नाटक महाभारत के युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर के अंतर्द्वंद्व को बखूबी उजागर करता है।

युद्ध के दौरान उनके द्वारा बोला गया वाक्य 'अश्वत्थामा हतो, नरो वा, कुंजारो वा' उनके मनोमस्तिष्क पर सदैव हावी रहता है, जिससे वे जीवन पर्यंत उबर नहीं पाते। जिस महाबली योद्धा अश्वत्थामा के संबंध में यह अधूरा सत्य युधिष्ठिर द्वारा बोला गया वह युधिष्ठिर के धर्मराज होने को पाखंड बताता है और द्रौपदी सहित श्रीकृष्ण पर भी अनुत्तरित प्रश्नों की बौछार करता है। रंगधर्मी अमलेश श्रीवास्तव के निर्देशन में नाटक अपने कथानक को बखूबी संप्रेषित करता दिखाई पड़ा। युधिष्ठिर की भूमिका में डॉ. जयंत रैना ने अंतर्द्वंद्व को प्रभावी ढंग से अभिनीत किया। युवा अभिनेता अमन श्रीवास्तव ने अश्वत्थामा की भूमिका के चरित्र को न केवल जीवंत किया बल्कि मुख्य पात्र के रूप में स्वयं को स्थापित किया। अनुभवी अभिनेत्री कुसुम मिश्रा ने द्रौपदी के जीवन के विविध रंगों को अपने अभिनय से निखारा। श्रीकृष्ण की भूमिका में शिवम पाण्डेय के अभिनय ने साक्षात भगवान का दर्शन कराया। संजय की भूमिका में अखिलेश सिंह ने अपनी अदाकारी से प्रभावित किया। राजलक्ष्मी मिश्रा ने राजगायिका के सधे हुए सुरों के साथ विक्षिप्त स्त्री के बेसुरे चरित्र को आत्मसात कर प्रभावी अभिनय किया। राजलक्ष्मी मिश्रा की दोनों ही भूमिकाएं भले छोटी थीं लेकिन उन्होंने जबरदस्त अभिनय और संवाद अदायगी से दर्शकों के बीच अपनी विशेष छवि बनाई। नाटक के बाद अतिथियों से लेकर आगतों तक ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। प्रतिहारी की संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण भूमिका के साथ उत्सव श्रीवास्तव ने अपनी विशेष छाप छोड़ी।

सेहत के प्रति जागरूक बनें महिलाएं: वानी

लहरतारा स्थित पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल अस्पताल में गुरुवार को सर्वाइकल कैंसर जांच, रोकथाम ओर जागरूकता सेमिनार हुआ। शुभारम्भ मंडल महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष वानी जैन ने किया। उन्होंने महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया। सर्वाइकल कैंसर की जांच कराने को प्रोत्साहित किया। शिविर में 47 महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जांच की। मुख्य वक्ता मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉ. ममता सिंह ने सर्वाइकल कैंसर के बारे में विस्तार से बताया। सीएमएस डॉ. आरजे चौधुरी ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर जागरूकता माह का उद्देश्य कैंसर के बारे में शिक्षा, एचपीवी टीकाकरण और नियमित स्क्रीनिंग (पैप स्मीयर) को बढ़ावा देना है। सेमिनार में एसीएमएस डॉ. आरआर सिंह, डॉ. कल्पना दुबे, डॉ. नीरज आदि ने सर्वाइकल कैंसर के प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया। अध्यक्ष ने मरीजों में फल वितरित किए। उन्होंने मैटरनिटी वार्ड में नवजात बच्चों को बेबी किट भेंट की। इस अवसर पर संगठन की सचिव जागृति सिंह, कोषाध्यक्ष मधुलिका सिंह, मौसमी चौधुरी, शालिनी पाल, गायत्री रामाकृष्णन, नम्रता सिंह, शालिनी अवस्थी, राशिका सिंह, श्रीवल्ली, अपर्णा साहा आदि सदस्याएं मौजूद रहीं।

रांची से त्रिपुरा-बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेजी जाती थी सिरप

कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी में सिद्धार्थनगर से नेपाल की सीमा से मंगलवार को गिरफ्तार विकास सिंह नरवे, अंकित श्रीवास्तव और आकाश पाठक को बुधवार को जेल भेज दिया गया। मामले में डीसीपी क्राइम सरवणन टी. ने पुलिस लाइन सभागार में बताया कि तीनों से पूछताछ में सामने आया है कि रांची स्थित भोला प्रसाद की फर्म शैली ट्रेडर्स से थोक में सिरप खरीदी जाती थी। यह खरीद पूर्वांचल के फर्मों के नाम पर होती थी लेकिन माल यहां न मंगाकर त्रिपुरा और प.बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेजा जाता था। उन्होंने बताया कि विकास सिंह ने बड़ागांव में देवनाथ फार्मेसी नाम से फर्म खोली और करीब 17 करोड़ का अवैध कारोबार किया। वहीं विकास के खास अंकित ने भी लगभग इतने का ही कारोबार किया है। दोनों की फर्म से छह-छह लाख शीशियों का कागजों पर कारोबार किया गया। दोनों ने शैली ट्रेडर्स से 34 करोड़ की कफ सिरप कागजों पर खरीदी और शुभम की मदद से बांग्लादेश भिजवाई। वहीं, आकाश पाठक ने नया नेटवर्क खड़ा करने लिए शुभम के साथ साझे की फर्म बनाई थी। बाद में शुभम से अनबन पर उसने जीएसटी सरेंडर कर दिया। खोजवां के दिवेश जायसवाल और सोनिया के अमित जायसवाल समेत अन्य के साथ मिलकर फर्जी फर्म खुलवाकर सिरप की तस्करी से सीधे तौर पर जुड़ा रहा। आकाश पाठक उर्फ लल्ली मैदागिन के सिद्धमाता गली गोलघर का निवासी है। वहीं विकास सिंह नरवे आजमगढ़ के बरहद के नरवे गांव का रहने वाला है। अंकित श्रीवास्तव जौनपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के ख्वाजा दोस्त निवासी है। आकाश और विकास पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। दोनों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी था। 200 करोड़ के कारोबार की पुष्टि एसआईटी प्रमुख डीसीपी क्राइम सरवणन टी. ने बताया कि शुभम और उसके सिंडीकेट से जुड़े अन्य आरोपियों की जांच में अब तक 92 लाख शीशी कफ सिरप की खरीद और अवैध बिक्री की पुष्टि हुई है। इसकी कीमत 200 करोड़ रुपये से अधिक है। बांग्लादेश सीमा के तीन तस्कर के नाम आए विकास सिंह और आकाश पाठक से पूछताछ में बांग्लादेश सीमा से लगे प. बंगाल के तीन अन्य तस्करों के नाम सामने आए हैं। ये शुभम के सिंडीकेट से जुड़े हैं। इनके जरिये ही अवैध रूप से सिरप की खेप बांग्लादेश पहुंचाई जाती थी। तीन दिन में दो बार कोशिश, नेपाल से भागते दुबई एसीपी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि तीनों ने सिद्धार्थनगर से दो बार नेपाल भागने की कोशिश की। चूंकि विकास और आकाश के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी था। इससे वह सफल नहीं हो सके। हालांकि पुलिस को जानकारी मिल गई थी कि आरोपी सिद्धार्थनगर में हैं। इस आधार पर कोतवाली पुलिस और एसआईटी पहुंची और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों नेपाल से दुबई भागने की फिराक में थे।

सर्वश्रेष्ठ वाद-विवादक गिरिराज तो सर्वश्रेष्ठ सांसद ममता बनर्जी बनीं

कानपुर। प्रमुख संवाददाता वीएसएसडी कॉलेज के रक्षा एवं सामरिक अध्ययन विभाग की ओर से चल रहे दो दिवसीय युवा संसद संवादपीठ का गुरुवार को समापन हुआ। जिसमें सर्वश्रेष्ठ वाद-विवादक का पुरस्कार गिरिराज सिंह बनी विदुषी शुक्ला को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार ममता बनर्जी बनीं शिवानी शर्मा को दिया गया। मौखिक प्रशंसा का पुरस्कार नितिन गडकरी बने आयुष तिवारी को और सर्वश्रेष्ठ पत्रकार का पुरस्कार हर्षित सिंह को दिया गया। वीएसएसडी कॉलेज में युवा संसद का आयोजन विभागाध्यक्ष डॉ. राम तिवारी के निर्देशन में किया गया। जिसमें प्रदेश के 20 से अधिक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की टीम के छात्रों ने हिस्सा लिया। गुरुवार को युवा संसद सत्र एवं शून्यकाल का आयोजन हुआ। जिसमें प्रतिभागियों ने संसद सदस्य की भूमिका निभाते हुए समसामयिक राष्ट्रीय विषयों पर तार्किक एवं तथ्यपरक विचार प्रस्तुत किए। इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ इंग्लैंड के वेलिंगबरो के मेयर राजकुमार मिश्रा ने किया और उन्होंने छात्रों से संवाद भी किया।

योगी सरकार का बड़ा फैसला:

30 प्रस्ताव मंज़ूर, शिक्षकों-रसोइयों को कैशलेस इलाज

यूपी की योगी सरकार ने शिक्षकों, शिक्षामित्रों के साथ ही शिक्षा विभाग के कर्मचारियों, रसोइयों को गुरूवार को बड़ी सौगात दी। योगी कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के टीचरों कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल बीमा सुविधा पर मुहर लगा दी है।

यूपी की योगी सरकार ने शिक्षा जगत से जुड़े लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह तय किया गया कि अब प्रदेश के माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मी और उनके आश्रित परिवार सरकारी के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष पांच सितम्बर को शिक्षक दिवस पर इसकी घोषणा की थी। अब योगी कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। शिक्षा विभाग के साथ ही अलग अलग विभागों से जुड़े 30 प्रस्तावों को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।कैबिनेट के फैसले से बेसिक व माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मी लाभान्वित होंगे। इस पर समग्र रूप से लगभग 448 करोड़ रुपये का व्यय होगा। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट के बाद प्रेसवार्ता कर पत्रकारों को शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के लिए शुरू होने वाले कैशलेस सुविधा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कैबिनेट के इस निर्णय के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबद्ध अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों एवं मानदेय शिक्षकों सहित), संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (मानदेय शिक्षकों सहित) को यह सुविधा मिलेगी। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा परिषद व संस्कृत शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त स्ववित्तपोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों को आईपीडी (अंत:रोगी विभाग) इलाज की कैशलेस सुविधा मिलेगी। इस सुविधा का लाभ उनके आश्रित भी उठा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि सरकार की इस पहल का लाभ 2.97 लाख से अधिक लोगों को मिल सकेगा, जबकि इस पर 89.25 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। इसी तरह, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित) में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत वार्डेन, पूर्णकालिक / अंशकालिक शिक्षकों / शिक्षिकाओं एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइयों और उनके आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि इस योजना से बेसिक शिक्षा परिषद के 11.95 लाख से अधिक शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मी लाभान्वित होंगे। सरकार की इस पहल से प्रति कर्मी करीब 3000 रुपये सालाना प्रीमियम के हिसाब से कुल 358.61 करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च अनुमानित है। कैशलेस इलाज की सुविधा सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ साचीज से जुड़े निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी। इलाज की दरें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तय मानकों के अनुसार होंगी। स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को वेरिफिकेशन के बाद योजना का लाभ मिलेगा। वेरिफिकेशन के लिए जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा।

TRANSFER

यूपी में बड़ा फेरबदल, एडीएम समेत छह पीसीएस अफसरों का तबादला

यूपी सरकार ने गुरुवार की रात प्रशासनिक विभाग में बड़ा फेरबदल कर दिया। शासन ने छह पीसीएस अफसरो के तबादले कर दिए। राकेश कुमार नगर मजिस्ट्रेट मथुरा एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट मंदिर परिसर मथुरा से एडीएम वित्त एवं राजस्व हमीरपुर व अनूप कुमार मिश्रा विशेष कार्य अधिकारी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर से नगर मजिस्ट्रेट मथुरा एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट मंदिर परिसर मथुरा बनाए गए हैं।राजेश कुमार एडीएम न्यायिक कानपुर नगर से एडीएम नागरिक आपूर्ति कानपुर नगर, महेश प्रकाश प्रतीक्षारत से एडीएम न्यायिक कानपुर नगर, रिंकी जायसवाल प्रतीक्षारत से मुख्य राजस्व अधिकारी गोंडा, अजय कुमार एसडीएम कानपुर विकास प्राधिकरण से अपर नगर आयुक्त नगर निगम फिरोजाबाद बनाए गए हैं। 20 दिन पहले यूपी सरकार ने चार आईएएस अधिकारियों के तबादले किए थे। कुमार प्रशांत को सचिव राज्य सूचना आयोग बनाया गया था। उनका तबादला पहले निदेशक समाज कल्याण से सचिव गृह के पद पर हुआ था, लेकिन कार्यभार ग्रहण न करने पर प्रतीक्षारत कर दिया गया। अब उन्हें तैनाती दी गई। उनके निदेशक समाज कल्याण रहते हुए अभ्युदय कोचिंग में कोर्स कोआर्डिनेटर के पदों पर भर्ती में गड़बड़ी उजागर हुई थी। राजेश कुमार द्वितीय महानिदेशक पर्यटन से सचिव उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग और डा. वेदपति मिश्रा सचिव उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग से महानिदेशक पर्यटन बनाए गए हैं। प्रांजल यादव से सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्रद्योग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है। वह सचिव सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन के पद पर बने रहेंगे।

मेरा काम करना अब मुश्किल...यूपी के एक और अफसर ने मांगा वीआरएस

यूपी के एक और अफसर ने वीआरएस मांगा है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता सिविल धर्मेश कुमार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लेटर 28 जनवरी को उपाध्यक्ष आनन्द वर्द्धन को दिया है। उपाध्यक्ष से उन्होंने वीआरएस की मंजूरी के लिए शासन को प्रत्यावेदन भेजने का अनुरोध किया है। अगले दिन उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए स्थानीय स्तर से शासन को प्रत्यावेदन भेज दिया गया। उधर, गुरुवार को सचिव पुष्पराज सिंह ने उनके सभी कामकाज को सहायक अभियंता अनिल कुमार को सौंप दिया है। धर्मेश को वाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया है। 58 वर्षीय सहायक अभियंता सिविल धर्मेश कुमार के पास रामगढ़झील ताल रिंग रोड की परियोजना देख रहे थे। इसके साथ ही खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना में बन रहे ईडब्ल्यूएस, एलआईजी एवं मिनी एमआईजी भवनों का चार्ज भी उनके पास था। कुछ दिन पहले ताल रिंग रोड का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनथ को निरीक्षण करना था। उसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री का निरीक्षण कार्यक्रम स्थगित हो गया था।

माघ मेला या मिनी कुंभ! तब साल भर में 5 करोड़, अब एक महीने में 18 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे

संगम का शहर प्रयागराज देश ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर आस्था और पर्यटन का बड़ा केंद्र बन गया है। कुछ वर्षों में यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बेहतर होती व्यवस्था के बीच महाकुंभ, माघ मेला और दूसरे धार्मिक आयोजनों ने संगमनगरी की वैश्विक पहचान को और मजबूत किया है। दिलचस्प बात यह भी है कि प्रयागराज में सर्वाधिक पर्यटक दक्षिण भारत से आते हैं। हाल के वर्षों में प्रयागराज में सुविधाओं के विस्तार से पर्यटकों की सालाना संख्या 5 करोड़ से ऊपर बनी हुई है। महाकुंभ वर्ष 2025 में लगभग 70 करोड़ लोग आए। इस साल तो माघ मेला भी मिनी कुंभ बन गया है, जहां अब तक 18 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं। यूपी पर्यटन विभाग के अनुसार वर्ष 2023 में 5.05 करोड़ भारतीय पर्यटक पहुंचे, जबकि विदेश से लगभग 4300 टूरिस्टों ने संगम और अन्य धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया। वर्ष 2024 में यह संख्या थोड़ी और बढ़ी। इस दौरान देश भर से 5.11 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज आए, वहीं विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़कर 7400 तक पहुंची। 2025 में महाकुंभ को लेकर देश भर से 68.95 करोड़ और विदेश से 20.54 लाख श्रद्धालु प्रयागराज आए। चालू वर्ष 2026 में माघ मेले के दौरान ही संगमनगरी में आस्था का अभूतपूर्व सैलाब दिख गया है।